External Affairs. I will find out what the current problem is.

Shri O. Rajagopal raised an issue of traditional fishermen not being benefited. I think the reply which I have given should be adequate to satisfy the hon. Member. Then he expressed a doubt — that may not be misplaced—that there are certain vessels which do not bring the catch to the mainland and they take it away. We have to find it out. If it has happened, it should be stopped.

As Shri Rajagopal said, the Murari Committee report has to be reconsidered. We are already doing it.

So far as coastal zone regulation is concerned, I have already stated all the dimensions of the problem. There has been a demand that the coastal zone regulation should not be enforced stringently. I had picked up a tiff with the Chief Minister of Kerala when I was on a visit. He was also trying to do that. This matter has to be settled in consultation with the Ministry of Environment. But we cannot be obivious to the environmental concerns. That is our prime concern because sustainability of these reserves depends on the conservation and preservation of fisheries wealth.

So far as welfare of fishermen, provision of drinking water, education and other things are concerned—Shri Raghavan and other hon. Members raised these issues—the State Governments are expected to come out with schemes. If they come out with feasible schemes, the Central Government would not be found lacking in assisting them.

Shri O. Rajagopal and Shri Salim said, "We are handing over everything to MNCs." I have never said that we are handing over anything to MNCs or any foreigners. At no stage we have said so. Rather I have been categorically denying it and there is no intention to do it. At least in our regime there has never been an attempt to do so.

So far as phasing out is concerned, I may say that the Murari Committee report has not given any cut-off date. Both of you were Members of that Committee. If you have any information, I would like to be enlightened on that. But the vessels presently operating under the lease arrangement would be phased out by the end of 2000. The permit of 19 vessels which are presently operating under the joint venture could be terminated only on violation of terms and conditions which I have already stated. If it is to be done individually, it will have to be done in consultation with the Law Ministry otherwise, they can run the vessels till they physically phase them out. The span is estimated to be around 10 to 12 years. I think I have covered all the points.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Shri Parmar raised a point about harassment to Indian fishermen.

श्री सोमपाल: इस संबंध में मुझे विदेश मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी। यह महत्वपूर्ण बात है। विदेश मंत्रालय के जिन प्रश्नों का आज मैंने लोक सभा में उत्तर दिया, उनके संदर्भ में मैंने यह पढ़ा जरूर है कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ कुछ बात हुई थी जिसमें से कुछ हमारी नावें जो उन्होंने गिरफ्तार की थी और जो हमने उनकी नावें गिरफ्तार की थी, आपस में उनकी अदला-बदली हुई है। कुछ मछुआरों को उन्होंने छोड़ा है और कुछ को हमने छोड़ा है। परन्तु यदि कुछ और है तो निश्चित रूप से इस संबंध में पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए। आपकी बात को मैं प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्रालय तक अवश्य पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: What about light indicators?

SHRI SOMPAL: This is one thing on which I am not in a position to say anything. I think there is a need for demarcating such things so that they do not stray into other areas and they do not run the hazard of being arrested by the alien Government.

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

On points arising of answer to Starred Question No. 325 given on 9th July, 1998 *regarding frequent* losses due to natural calamities

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला** (हरियाणा): थैंक यू मि॰ वाइस चेयरमैन महोदय, 9 जुलाई को इस सदन में 325 नंबर का जो सवाल था, स्टार्ड क्वेश्चन, जो कुदरती आपदाओं के कारण जान-माल , फसलों, मकानों और पशु धन के भारी नुकसान के बारे में था कि सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है, यह सवाल था। लेकिन जो उस समय मंत्री थे उनका जवाब कतई तौर से हाउस को आश्वस्त नहीं कर सका, इसलिए चेयरमैन साहब ने इस बात की परमीशन दी कि अगर आप हाफ एन आवर डिसकसन की रिक्वेस्ट करेंगे तो वह स्वीकार करेंगे।

**(उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए)** मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, हम आज इक्कसीवीं सदी के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन आज भी कृषि को कुदरती आपदाओं से जो भारी क्षति पहुंच रही है उसके लिए न तो साइंस, न टेक्नालाजी, न मौसम विभाग, न न्यूक्लियर टेक्नोलाजी, न रिसर्च, कोई भी साइंस का विंग इस बारे में किसान की मदद करने के लिए नहीं आया है। कोई भी ऐसी योजना नहीं बनी है जिस के आधार पर किसान राम भरोसे न रहे। कुदरत के ही भरोसे आज भी किसान रह रहा है। यह जो सारी टेक्नालाजीज हैं, माडर्न साइंस है, इससे दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बाते हुई हैं। कम्युनिकेशन जगत ने, टेलीफोन है, सेलुलर फोन है और कई दूसरी बातों में, बहुत उन्नति की है। महोदय, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है तो उसे क्यों इससे वंचित रखा जा रहा है? इस देश के करोड़ो-अरबों रुपए की सम्पत्ति, उनकी जान, मकान और पशुधन का, जो फ्लड या इस तरह की जो दूसरी आपदायें है, उससे नुकसान हो रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा। महोदय, इस साल को ही अगर आप देख लें, इस वर्तमान समय के लिए मौसम विभाग ने बार बार इस देश के किसानों को यह बताया कि इस साल वर्षा जो है वह औसत से ज्यादा होगी। मानसून अच्छा है इसलिए कोई चिंता की बात नहीं हैं। लेकिन आज की हालत मैं बताना चाहूंगा। सरकार के पास समय तो थोड़ा है इस चीज को देखने के लिए लेकिन करने के लिए उसके पास समय है ही नहीं। आज पूरे नार्थ इंडिया में अरबों एकड़ जमीन, नार्थ के बारे में मैं कह सकता हूं, जिसमें यू॰पी॰ के कृषि मंत्री महोदय का जो अपना इलाका है, राजस्थान के इलाके, सम्पूर्ण हरियाणा और पंजाब और बहुत से इस देश के इलाके होंगे, साउथ में भी बहुत इलाके हैं। जहां धान की फसल, जीरी की फसल इस वक्त लगाई जाती है। अगर सबसे ज्यादा पानी किसी फसल को चाहिए तो वह धान और जीरी की फसल है। इसके ऊपर रुपया भी किसान को बहुत खर्च करना पड़ता है। मुझे बड़ा भारी दुख है, आप चले जाइए यहां से हरियाणा और पंजाब, ट्रेन से चले जाइए, कार से चले जाइए, पिछले तीन हफ्तों से मानसून की एक बूंद भी जमीन के ऊपर नहीं बरसी है। अगर बरसी है तो वह केवल दिल्ली के शहरों में बरसी है। लेकिन खेतों में नहीं बरसी है। इसका नतीजा यह है कि धान के खेतों में, जीरी के खेतों में जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं दरेड़ें फट गई, जमीन के बीच में 4-5 इंच जमीन जो है उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। नतीजा यह है कि अगर किसान भारी खर्च करके, डीजल सेट लगाकार पानी डालने की कोशिश करता है तो वह पानी उनके अंदर चला जाता है। इसके कारण जो जीरी है वह तकरीबन सूख गई है। अगर एक हफ्ते या दो हफ्ते बरसात नहीं हुई तो नार्थ इंडिया के अंदर जीरी का एक दाना भी होने वाला नहीं है। मैं आपको पंजाब और हरियाणा की दशा बताता हूं। मंत्री महोदय, भी एक किसान है। मेरी पत्नी खेती करती है इसलिए जहां दूसरों का, लाखों करोड़ों का दर्द मेरे अन्दर है, मेरा भी एक छोटा सा परिवार है। मैं यह बात यहां केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यह बात दुख में कहने लग रहा हूं। आज किसान आसमान की तरफ देखने लग गया है। सच पूछों तो उसके आंसू सूख गए हैं ऊपर देखते देखते लेकिन बूंद नहीं पड़ी है। बिजली का तो नाम नहीं है पूरे नार्थ इण्डिया में, ट्यूबवेल का कनेक्शन 25 हजार रुपये लगा कर डीजल इंजन लगा कर लेना पड़ा है, उधार ले कर, अंगूठा लगा कर सैकड़ों रुपये का डीज़ल रोज़ जला कर वह बेचारा जिस जीरी पर, धान पर इतना रुपया खर्च कर चुका है, उसको बचाने के लिए उसका पूरा परिवार लगा हुआ है। लेकिन उसका कोई भी इलाज नहीं है। नहरों में पानी नहीं है। ट्यूबवेल में बिजली नहीं है। बरसात हुई नहीं है। आप साइंस और टेक्नोलोजी पर अरबों-खरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। मौसम विभाग यह कह दे कि भाई इस बार पर्याप्त मात्रा में बरसात नहीं होने वाली है तो मुझे पता है कि किसान सारी जमीन में जीरी या धान की फसल नहीं बोता। कपास की फसल तीसरे साल निरंतर भारी खतरे में है, सूखने का खतरा है। उसका कारण यह है कि पानी नहीं है। न्युक्लियर टेक्नोलोजी है, आपने परमाणु विस्फोट किया है हमारे देश में, अगर इस टेक्नोलोजी को पानी के लाने के लिए, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए किसी तरह का इंतज़ाम आप करते या बिजली के बड़े बड़े संयंत्र लगाते तो शायद किसान को इस दशा से बचाया जा सकता था। मैं

आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री चाहे दिल्ली का हो या हरियाणा का हो, चाहे सेंटर का कोई मंत्री हो, आज कल तीज का त्यौहार है, आपने अखबारों में फोटो देखे होंगे, झूले झूल रहे हैं औरतों के बीच में मुख्य मंत्री जलेबियां खा रहे हैं और उधर किसान आत्म हत्याएं कर रहे हैं **(व्यवधान)**

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)** : तीज तो फेस्टीवल है, यह कोई नेचुरल क्लेमिटी तो नहीं है।

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:** फेस्टीवल है, अच्छी बात है लेकिन जब लोग मर रहे हों तो कम से कम राजनेताओं को यह अधिकार नहीं है, उनका यह धर्म नहीं है कि झूले झूलें, गीत गाएं और डांस देखें और जलेबियां खाएं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। आम जनता फेस्टीवल मना सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा सरकार से कि पिछले दो साल में पूरे नार्थ इण्डिया की कपास की फसल बरबाद हो रही है। पाकिस्तान के बार्डर से ले कर तमिलनाडु तक चले जाइये किसी भी प्रान्त में दो साल से कपास की फसल पर पेस्ट का अटैक हो रहा है, इरेटिक वैदर, अनसीज़नल रेन, कलाउडी वेदर के कारण किसान की कपास की फसल नहीं हुई है। इस साल सूखे की स्थिति है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके रिलीफ के स्कोप को सरकार वाइडन करे और इसमें पेस्ट अटैक इतना वाइडस्प्रेड होता है जब टेम्परेचर लो होता है, बादल होते हैं, कई-कई दिनों तक बादल रहते हैं, यह पेस्ट इतना ज़बरदस्त ग्रो करता है एक घंटे में कई मिलियन की संख्या में ग्रो करते हैं, कोई भी फसल हो उसका एक भी दाना तक नहीं बचता है। इसका अटैक हरी सब्जियों पर और हरे चारे पर भी बहुत ज्यादा होता है।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please be brief and conclude now.

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:** सरकार ने कोई भी मदद नहीं की है। प्रान्तीय सरकार और भारत की सरकार ने कोई मदद नहीं की है। उपसभाध्यक्ष महोदय,मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैंने समय बचाने के लिए मंत्री महोदय से अभी संक्षेप में बात की। मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि कीड़ों के प्रकोप, बेमौसमी बरसात को कुदरती आपदाओं के दायरे में लाना चाहिए।

मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने ऐसा करने का विश्वास भी दिलाया है और शायद इनका ख्याल यह है कि यह पहले भी कवर्ड है। लेकिन मुझे पता है कि आज तक कीड़ों के प्रकोप से हुए किसी नुकसान का मुआवजा या नुकसान पर कोई मदद नहीं मिली। कुदरती आपदाओं के वर्तमान जो मापदण्ड हैं, इनका जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, कृपा करके उन रूल्स को जो बहुत पुराने बने थे, सालों साल पहले उनको बदलिए। किसान उसमें फार्म नहीं भर सकता है। पटवारी के पास जाएगा तो पैसे मांगेगा। तहसीलदार के पास जाएगा तो पैसे मांगेगा। उसके बाद किसी और जगह जाएगा दफ्तरों में। आप इस प्रोसीजर को सिमपलीफाई करिए। सीधे किसान को उसका मुआवजा या जो सरकार मदद देना चाहे, वह मिलनी चाहिए। उसका स्कोप भी वाइडन करें। दायरे को भी ज्यादा बढ़ाएं। इस वक्त उसका दायरा बड़ा सीमित है। जो रकम मिलती है उस रकम से तो उपसभाध्यक्ष महोदय, पानी भी नहीं पी सकता है किसान का परिवार। उसकी फसल का नुकसान, थोड़ा-बहुत और आगे के लिए खेती के लिए वह कोई साधन जुटा सके, यह देखकर कि आज रुपए की कीमत इस देश में क्या है— और रुपया मिलता कितना है— इसलिए कृपा करके रुपए की कीमत को देकर, फसलों में डलने वाली इनपुट्स का जो भाव है वह देखकर, आज जिंदगी वहन करने के लिए जो आसमान छूती महंगाई है उसको देखकर, इसका स्कोप आप तय कीजिए। आप नौजवान हैं। आपके दिल में तड़प है। लेकिन आपको अधिकार नहीं है। हमने बहुत कोशिश की आज बारी-बारी इस सदन में। ये पूरा मंत्रालय चलाने में सक्षम है। प्रधान मंत्री बेचारे को कहां समय है। प्रधान मंत्री की एक टांग और एक आंख तामिलनाडु की तरफ है और दूसरी आंख आपके प्रांत की ओर है ...**(व्यवधान)**... फाइलें कहां देख सकता है प्रधान मंत्री। तो पता नहीं उनको क्या संकोच है इसमें कि एक नौजवान को, पढ़े-लिखे को, सक्षम आदमी को ...**(व्यवधान)**...

**श्री सोमपाल:** इतनी दया आ रही है तो कुछ सोचें इस विषय में भी— जरा समर्थन करने की बात जिससे क्षमता बढ़े काम की ...**(व्यवधान)**...

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:** समर्थन। उपसभाध्यक्ष महोदय गवाह है मैं पांचवी बार यह बात कह रहा हूं। पता नहीं आप समर्थन किस बात को मानते हैं। मैं लड़ाई तो नहीं करता उनके साथ।

**श्री सोमपाल:** नहीं, मेरा समर्थन नहीं, सरकार का।

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:** आप सरकार ही हैं। किसानों में मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि वे गरीब हैं, बहुत हैं। सरकार की भी इसमें मदद होगी।

आपको अधिकार होंगे तो लोग खुश होंगे और सरकार को फायदा होगा।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा उपसभाध्यक्ष महोदय कि फसलों की बीमे की जो स्कीम है वह बहुत सिम्पलीफाई करें जिसमें व्यक्तिगत किसान के नुकसान की बात को भी आप कवर करें। यह नहीं कि पूरी तहसील में नुकसान होगा तब फिर किसान को किसी अनुपात से 2—4 रुपए आप देंगे या उसने जो लोन ले रखा है वह छोड़ देंगे। आप सही मायनों में हमको विश्वास है कि प्रयत्न करेंगे। इस बात का कि एक नयी बीमा योजना लागू की जाए।

कोआपरेटिव और नेशनलाइज्ड बैंक्स से किसान को मिलने वाले कर्ज की ब्याज की दरें अगर 18 और 24 प्रतिशत रहेंगी तो मैं किसी भी आदमी को कन्विंस कर सकता हूं कि किसान की खेती घाटे का, नुकसान का धंधा रहेगा। कोई किसान अपने कर्ज की किस्तें वापस नहीं दे सकता है। मैंने पहले भी यह कहा है। मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। आज ऐसा कानून है कि नेशनलाइज्ड बैंक्स दाम वगैरह मांगते हैं। 24 परसेंट उनका चक्रवर्ती ब्याज है। एक किसान ने अगर 3 लाख रुपए लिया तो 6 लाख देकर भी 3 लाख रुपए उसके अभी बाकी होते हैं। यह कौन-सा इन्साफ है कि प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट ले कोई। यह तो साहूकार को भी नहीं लेना चाहिए और आज के युग में आपके भारत सरकार के बैंक ऐसा लें। मुझे उम्मीद है कि आप यह भी करवाएंगे। आप यह भी करवाएंगे कि किसानों की गिरफ्तारी कोआपरेटिव बैंक्स द्वारा न हो। आज विधान कहां गया इस देश का। 40 दिन के लिए रिमांड? पेश भी नहीं करना? कोआपरेटिव का सबसे जूनियर आदमी, सब-इंस्पेक्टर पकड़ता है। सिविल जेल का नाम गलत लिखा हुआ है। मैं शर्त मारता हूं अगर आज कोई भी सिविल जेल है छोटी जगह पर। दफ्तर की एक काल कोठरी में जिसमें न टायलट है, न यूरिनल है, न सांस आती है, न पंखा है, उसमें बंद करके, ताला मार कर और जो चौकीदार है दफ्तर का बंदूक वाला वह बाहर खड़ा रहता है, पानी मिल नहीं सकता, खाना मिल नहीं सकता, खाना उसके घर वाले दे रहे हैं, लेकिन खाने का सारा खर्चा उसके कर्जे के अंदर लिख दिया जाएगा कि इसने इतने रुपये का खाना खाया था। आप इस काले कानून को तो खत्म करवाइये। आप नौजवान हैं नहीं तो लोगों को क्या जवाब देंगे कल जब यहां से जायेंगे और मंत्री नहीं होंगे?

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि आज नेशनालाइज्ड बैंक्स हजारों हजार किसानों की कुरकी करवा कर, गांवों के अंदर जपीन की नीलामी करके ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: यह लॉसेज़ इयू टू नेचुरल कैलामिटीज़ पर है ...(**व्यवधान**)...

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला**: फिर उसके रिज़ल्ट क्या हैं, उसके बाद क्या होने लग रहा है ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: समस्या तो है, सुरजेवाला जी, ...(**व्यवधान**)... आप इसके बारे में फिक्र मत करिए, लेकिन सारी समस्या तो आधे घंटे के डिसकशन में आ नहीं सकती।

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला**: हां, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो कैलामिटी से साइंस लड़ पा रही है और न सरकार लड़ेगी, तो फिर ठीक है लोग आत्महत्या ही करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगली बात मैं यह कह कर अपनी बात खत्म, करता हूं कि ब्याज़ की दर 6 परसेंट से फालतू नहीं हो, किसान की गिरफ्तारी और जमीन की नीलामी बंद हो। उसके साथ-साथ जो आपकी जितनी नई टैक्नोलोजी है वह सारी की सारी किसान को बचाने के लिए, उसकी फसलों को, उसके जानवरों को बचाने के लिए और दूसरे जो गरीब लोग हैं उन सब को इन कुदरती आपदाओं के हमले से बचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाए।

**(उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए**

दूसरे हरित क्रांति अगर नहीं होगी तो कोई भी कुदरती आपदा के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। किसान की एक किले में जब तक 50 हजार रुपये का एक फसल में आमदनी का आप प्रावधान नहीं करेंगे, वह स्तर नहीं ले जायेंगे, तब तक कुछ फायदा नहीं है। Modernisation of agriculture, changing of cropping patterns, change of cold storages, processing units, packaging units, all these inputs are spurious and the *kisan* is being cheated very badly. Then I would like to say.

एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय, आज सब से बड़ी मार किसान को मंडी की है। यह फ्री मार्केट है उपसभाध्यक्ष महोदय, मतलब फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस और फ्री प्ले आफ मार्केट फोर्सेस कौन है किसान समझ सकता है, मैं तो समझ नहीं सका 6 साल आपके पास रहते हुए,

उपसभाध्यक्ष महोदय, कोई आप जैसा बेशक समझता हो, यह मल्टी नेशनल कंपनीज़ है, और कोई नहीं है। यह स्टाक एक्सचेंज है मुम्बई का, टोकियो का, लंदन का, न्यूयार्क का, देश की मंडियों का फैसला तो वे करते हैं कि किसान को क्या मिलेगा, मछुआरे को क्या मिलेगा, आज कपड़ा बुनने वाले को क्या मिलेगा या किसी को क्या मिलेगा। इंडस्ट्री वाले तो कह रहे हैं कि हमको केवल लेवल प्ले ग्राउंड चाहिए जो करोड़पति हैं उनको तो भारतीय कंपनियों से भय है। किसानों को क्या चाहिए, ग्राउंड की बजाय किसान को कम चाहिए। कौन सी मार्केट फोर्सेस से फ्री मार्केट में आज किसान भाव लेने के लिए लड़ सकता है? महोदय, इसलिए मेरी दरख्वास्त है इस सरकार से कि जब फॉर्मर फ्रेंडली मार्केट नहीं होगी, जब तक किसान दोस्त मंडी इस देश में नहीं होगी और किसान की जब तक उसके अंदर आवाज़ नहीं होगी उस मंडी में कीमतों का फैसला करने के लिए कि किसका क्या खर्चा और किसको क्या आमदनी होनी चाहिए और किसको कैसे उसकी भरपाई करनी चाहिए, उसको करे बिना इस देश का किसान मरने लगा है और मर जाएगा। अगर वह मर गया तो यह देश भी जिंदा नहीं रहेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल):** उपसभाध्यक्ष महोदय, स्व० राजीव गांधी जी ने किसी एक स्टेज के ऊपर, किसी एक समय के ऊपर एक वाक्यांश का प्रयोग कर दिया कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और यह कांग्रेस वालों के लिए एक मंत्र बन गया, जो खड़ा होगा 21वीं सदी में जाएगा जहां तक हमारे काल की गणना का सवाल है ...(व्यवधान)

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:** 18वीं सदी में तो हम इस मुल्क को ले जायेंगे नहीं, यह तो मैं विश्वास दिला सकता हूं। हम वक्त के पहिए को किसी तरह वापस नहीं ले जाना चाहते, हम आगे ले जायेंगे।

8.00 P.M.

**श्री सोमपाल:** कठिनाई यह है कि जिस मानसिकता से वे ग्रस्त हैं, उस का आरोप हमारे ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं। यह जितनी भी विकृतियां यहां पैदा हुई हैं, जो ये बार-बार कहे जा रहे हैं, वह सारा लगभग इन का कार्यकाल रहा है। यह स्वयं हरियाणा में मंत्री रहे हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:** पिछली बात कहकर सरकार कितने दिन पर्दापोशी करेगी, जिम्मेदारी से भागेगी। Governance is a continuous process. You have to answer the questions. You are responsible for that.

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** सुरजेवाला जी, बैठिए।

SHRI SOMPAL: I will answer every query which he has raised and every phenomenon which he has indicated in his speech.

पर चूंकि इक्कीसवीं सदी की बात कही, हमारे काल की गणना तो दूसरे तरह की है। यह पाश्चात्य मानसिकता का द्योतक है जिस से आप ग्रस्त रहे हैं। हमारे हिसाब से तो यह लाखों वर्ष पुरानी सभ्यता है। इस ने इक्कीसवीं सदी नहीं, कितनी सदियां पार की हैं और इसी तरह सफलतापूर्वक पार करते चले जाएंगे।

जहां तक कृषि का प्रश्न है, आप ने कहा कि यह प्रकृति के ऊपर आधारित है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं और आप स्वयं मानेंगे कि कृषि स्वयं अपने आप में एक प्राकृतिक व्यवस्था है।

आप जानते हैं कि यह प्रकृति के ऊपर आधारित है और तीन प्राकृतिक संसाधनों—भूमि, जल और जैविकी संपदा के संयोग और संयोजन से मानव के द्वारा जैविक उत्पादों की व्यवस्था और प्रयास या उद्यम का नाम कृषि है। तो यह कह देना कि यह सर्वथा प्रकृति से हट जाएगी, संभव नहीं है, न कभी हुआ है, न होने वाला है क्योंकि यह स्वयं में एक प्राकृतिक व्यवस्था है।

जहां तक प्राकृतिक आपदाओं का प्रश्न है, यह भी बात सर्वमान्य है कि किसी भी विकसित-से-विकसित देश में जिस ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी में बहुत तरक्की कर ली है, प्राकृतिक आपदाओं से कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। परंतु मानवीय प्रबंधन के माध्यम से उन की विभीषिका को, उन के प्रभाव को कम करने का काम अवश्य किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पूर्व चेतावनी के माध्यम से प्रभावित होने वाले लोगों को नए संचार माध्यमों के द्वारा और मौसम विभाग की पूर्व चेतावनी के द्वारा कहा जा सकता है। दूसरे जो प्रबंध है जिस में राहत की बात आती है, उन से कैसे बचा जाए या जैसे बाढ़ आने पर गांव को ऊपर उठाया जाए, पानी की निकासी का प्रबंध कैसे किया जाए, फसल-चक्र का संयोजन इस प्रकार से किया जाए कि जब वह प्राकृतिक आपदा या बाढ़ जैसे आती है, उस

समय को बचाकर फसलें बोई जाएं। इस तरह के मानवीय उपक्रमों के माध्यम से इस के दुष्प्रभावों को कम करने की कोशिश जरूर की जा सकती है।

जहां तक प्राकृतिक आपदाओं से क्षति का प्रश्न है, यह बात सभी जानते हैं कि उस में जन-धन, जान-माल की क्षति होती है, मकान भी गिरते हैं, पशु भी मरते हैं, मनुष्य भी मरते हैं और उस कारण न केवल मानसिक और शारीरिक क्लेश आते हैं, बीमारियां आती हैं, परंतु उस के आर्थिक दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे बेरोजगारी आती है, उत्पादन घटता है, खाद्यान्न की उपलब्धता और दूसरे कच्चे माल की उपलब्धता घटती है, कीमतों पर असर पड़ता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और निर्यात भी प्रभावित होता है।

जहां तक मौसम विभाग की रिपोर्ट की बात है चौधरी शमशेर सिंह जी सुरजेवाला ने कहा कि अगर वह ठीक से रिपोर्ट कर देते तो शायद धान की फसल उतनी ज्यादा नहीं बोई जाती। कौन सी फसल किसान बोता है, यह अकेले मौसम विभाग की चेतावनी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, यह आप भी जानते हैं। यह उस के पुराने वर्षों के अपने अनुभव पर भी निर्भर करता है कि किस फसल को बोने से उस को स्थिर उत्पादन मिलेगा और उस से कितनी आय होगी, उस की क्या कीमत चल रही है और कौन सी फसल वह बोए। कपास उत्पादकों के पिछले दो या तीन वर्ष के अनुभव से ज्ञात हुआ कि उन को बार-बार कीटों, परजीवियों व अन्य बीमारियों, सूखा और असामयिक मौसम की गड़बड़ी जिसमें कुसमय वर्षा की भूमिका भी रही। इन से फसलों को हुई क्षति के कारण उत्तर भारत और विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के श्रीगंगानगर आदि जिलों के लोगों को यह अनुभव हुआ कि इस फसल में प्रायः इस प्रकार की क्षति होती है, इसलिए दूसरी फसल बोई जाए। तो मैंने यह बात देखी है कि इस बार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में जहां-जहां सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित है, वहां धान का क्षेत्रफल बढ़ा है और कपास का क्षेत्रफल घटा है।

जहां तक धान की फसल को नुकसान होने का प्रश्न है, अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, उस में केवल उड़ीसा, बिहार का पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के समुद्र तटीय किनारों को छोड़कर वर्षा के अभाव की कहीं से सूचना नहीं है। सभी जगह वर्षा सामान्य है। जहां तक उत्तर भारत का और मध्य भारत का प्रश्न है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अभी तक सामान्य वर्षा हुई है और पिछले दो हफ्तों की भी जो रिपोर्ट हैं और जो 35 डिवीज़न हैं, उनमें से 22 में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। कुछ में कम हुई है, पर बिल्कुल अभावग्रस्त क्षेत्र बहुत थोड़े हैं, जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया। ...(व्यवधान)... जो मानसून अभी एक्टिव हुआ है पिछले दो दिनों में, आशा यह है कि हरियाणा और पंजाब के इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी। मैं भी अभी 26 तारीख को दिन में वापिस आया हूं, संगरिया से लेकर आपके पूरे क्षेत्र में — डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी रोहतक, पूरे क्षेत्र में कहीं-कहीं ऐसे लक्षण जरूर हैं कि वर्षा की आवश्यकता है तुरंत और अगर 10—15 दिन में नहीं होती तो बड़ी मुश्किल होगी, आपकी बात ठीक है, पर कहीं मोटी तरेड़-चरेड़ पड़ी हों, कम से कम इस इलाके में मैंने नहीं देखा। ...(व्यवधान)...जीरी का इलाका है साहब। नाली का जो झज्जर का इलाका है, चौधरी साहब, वह छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, मैं देखकर आया हूं, सैकड़ों किलोमीटर तक जीरी-जीरी बोई है। वहां काफी है और बहुत सारे मिल भी हैं। यह बात ठीक है कि आपका जो क्षेत्र है जींद, कोलायत, पेवाड़, झांड, कोल, उस तरफ ज्यादा चला जाता है, पर इस तरफ भी काफी होती है।

जहां तक कपास की फसल को होने वाले परजीवियों और कीटों के आक्रमण से क्षति का प्रश्न है, जैविक नियंत्रण की आवश्यकता पर आपने बल दिया, हम इस बात से सहमत हैं क्योंकि जो रसायनिक पदार्थों का उपयोग होता है उसके कारण कई तरह के असंतुलन वातावरण में, मृदा में और जल में और विषैले तत्वों के अवशेष खाद्य ऋंखला में और दूसरे पीने के पानी में जाने के कारण काफी कठिनाइयां पैदा होती हैं। तो जैविक नियंत्रण की आवश्यकता है और इस संबंध में सरकार सचेत है और हम इस संबंध में बहुत व्यापक योजना इसके लिए तैयार कर रहे हैं पहले से भी। यह जो बाइलॉजिकल कंट्रोल है, उसमें तीन इस तरह के हमने जैविक नियंत्रण चिन्हित किए हैं। एक तो एन०पी०वी० है — न्यूक्लियर पोली हाइड्रो वायरस, जो लीफ कर्ल को, जो वायरस की एक बीमारी है जीवाणु की, उसको नियंत्रित करता है। दूसरा जो जड़ की गलन की बीमारी है कपास में, उसके बीज को इसी चीज से ट्रीटमेंट देने से वह हट सकती है, उसका भी हमने विकास किया है और दो और इसी प्रकार के प्रीडेटस हैं, जो इन परजीवियों को, इन पेस्ट्स को और कीट को खा जाते हैं, इसमें एक ट्राइकोग्रोमा है और एक दूसरा है, जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, उनके अंडों से लेबोरेट्री के

अंदर तैयार किया जाता है और अगर एन०पी०वी० की बात हो तो केवल दस कार्ड जिनके ऊपर अंडे पेस्ट होते हैं, अगर एक एकड़ में लगाए जाएं तो वह पूर्ण नियंत्रण लीफ कर्ल डिसीज़ का कर सकता है बिना रसायनिक खाद के और केवल 50 रुपए में ऐसा हो सकता है। दूसरा इसी प्रकार का परजीवी नाशक है जो 170 रुपए में एक हैक्टेयर की खेती को बना सकता है। तो उस संबंध में सरकार उनके पर्याप्त उत्पादन का प्रयास करेगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि 26 तारीख को संगरिया में हमने एक अंतर्राज्यीय सम्मेलन और एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था, वह मेरी पहल के ऊपर किया गया था जिसमें आपके यहां के कृषि निदेशक, राजस्थान के व पंजाब के कृषि निदेशक और वहां के कृषि मंत्री, श्री अमर राम जी और पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरूदेव सिंह जी बादल, ये सब पधारे थे। उसमें किसानों को इस संबंध में जानकारी दी गई और इस प्रकार की गोष्ठियों को नियमित रूप से फसल बोने से पहले और एक बार फसल के बीच में करने की हम कोशिश करेंगे। जहां तक परजीवी या कीटों के आक्रमण से होने वाली फसलों की क्षति को प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में सम्मिलित करने का प्रश्न है, मैं आपको सूचित कर चुका हूं निजी रूप में और यहां पुनः उसको कहना चाहता हूं कि यह पहले से ही, पिछले साल से, उसमें सम्मिलित कर दी गई है। ऋण की उपलब्धता और क्षति-पूर्ति को बढ़ाने के लिए हमने एक समिति पहले से बैठा दी है और वह इसके मानकों के ऊपर पुनर्विचार करेगी। यह बात सही है कि आपकी अभी तक जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की उपसमिति उसका प्रशासन करती है, उसके मानकों के अनुसार 500 रुपया प्रति हैक्टेयर से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। यह निश्चित रूप से बहुत न्यून है। उन मानकों को संशोधित करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए और नए मानक सुझाने के लिए समिति बैठी है, दो-तीन महीने में उसका प्रतिवेदन आएगा और उसके अनुरूप उन्हें बढ़ाने का काम किया जाएगा।

जहां तक आपने ऋण की सुलभता की बात कही है, इसमें दो मत नहीं हो सकते कि ऋण पर्याप्त मात्रा में मिले, उपयुक्त समय पर मिले और सरल प्रक्रिया के माध्यम से कमजोर से कमजोर किसान को सुलभ हो। इस संबंध में क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की थी और उसको हम इसी वर्ष लागू करने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक और जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, नाबार्ड है, सबको इसके संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। उसमें किसान की परिसंपत्तियों को देखते हुए, उसकी उत्पादन क्षमता को देखते हुए ऋण दिया जाएगा और ऋण की अदायगी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक सीमा बांध दी जाएगी और उस सीमा तक किसान कभी भी ऋण ले सकता है और वापस कर सकता है। आपकी पहले वाली परंपरा जो 50 साल तक रही है कि जब एक-एक रुपया वापस न हो जाए, तब तक उसे और ऋण नहीं मिलेगा, उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। यह सारी कार्यवाही हम इसी वर्ष में करेंगे।

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:** ब्याज की दरों के बारे में आपने नहीं कहा।

**श्री सोमपाल:** मैं उसी पर आ रहा हूं। आपका जो सुझाव है 6 प्रतिशत का, वह वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है क्योंकि हमें चिंता ज्यादा उस किसान की है जिसको महाजनों के पास 36 परसेंट से लेकर 48 परसेंट और 60 परसेंट तक ब्याज देने के लिए विवश होना पड़ता है। उसको यदि 12 प्रतिशत या 14 प्रतिशत वाला ऋण मिल जाए तो ज्यादा राहत मिलेगी बजाय इसके कि जिसको पहले से 12 प्रतिशत या 14 प्रतिशत पर ऋण मिलता है, उसको 6 प्रतिशत पर मिल जाए। महाजन की भूमिका आज भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वह 70 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराता है। हम पहले ऐसे लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं।

महोदय, जहां तक ब्याज की दरों को नीचे करने की बात है, सभी इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। उसमें एक कठिनाई है और चौधरी साहब, आप भी इससे सहमत होंगे और इस बात को एप्रिशियेट करेंगे कि हमारे देश में ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति की दर 8-9-10 प्रतिशत रही है। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसे मुद्रास्फीति से एक-दो प्रतिशत ज्यादा न मिले, बैंक में सावधिक जमा में पैसा जमा नहीं कराएगा और जब तक सावधिक जमा नहीं होगी, तब तक बैंकिंग व्यवस्था चल नहीं सकती और बैंक को उसके ऊपर कुछ ब्याज की दर निर्धारित करनी पड़ेगी। तो इसमें काफी राहत लगेगा क्योंकि मुद्रास्फीति की दर को 3-5 प्रतिशत करके ही यह दर नीचे लाई जा सकती है। यह एक दिन में संभव नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उस ओर प्रयासरत हैं।

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:** मंत्री महोदय, मैं जागीरदारों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं छोटे किसानों के लिए बोल रहा हूं।

श्री सोमपाल: मैं भी उसी छोटे किसान के लिए बोल रहा हूं जो महाजनों के चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसे किसान को 60 प्रतिशत से 15 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

आपने जहां तक भंडारण की व्यवस्था की बात कही है, हम जो कृषि नीति बनाने जा रहे हैं, उसका यह एक अभिन्न अंग होगा और शीत भंडारण बनाए जाएंगे और ये सारे ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। आपकी सरकार की तरह दिल्ली में भंडारण नहीं होंगे जहां 50-60 हजार रुपया प्रति गज भूमि मिलती है। उन भंडारणों में किसान अपनी चीजें रख सकते हैं और जो रसीद मिलेगी, उसके आधार पर वे ऋण ले सकते हैं। यह हम करने जा रहे हैं।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: मंत्री महोदय, किसानों की गिरफ्तारी और किसानों की जमीन की जो नीलामी है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं।

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, कठिनाई यह है कि प्राकृतिक आपदा का एक सीमित सा प्रश्न और विषय हमारे सामने था पर माननीय चौधरी साहब ने जिनकी कृषकों के प्रति चिंता सर्वविदित है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं वे पूरी कृषि नीति के सारे आयाम इसमें ले आए हैं जिन्हें यहां नहीं जोड़ना चाहिए। इससे आज के विषय से कुछ अंतर हो जाता है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने बात कही है किसान की गिरफ्तारी की, इस बात को माननीय वित्त मंत्री जो अपने बजट भाषण में स्वयं कह चुके हैं कि इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ग्रामीण ऋणों की वसूली की प्रक्रिया को सहज और किसान के पक्ष की बनाने और किसान के उत्पीड़न को रोकने के संबंध में हम आवश्यक कदम उठाने जा रहे हैं और नयी ऋण नीति का यह एक अंग होगा। जहां तक विपणन की बात है, यह बात आपने सही कही कि ...(व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: चाईस चेयरमैन साहब, आपकी इजाजत से मैं यह कहना चाहता हूं कि बी॰आई॰एफ॰आर॰ है इंडस्ट्रीज के लिए। मेरा पूरा ऋण माफ हो जाएगा अगर मेरी बेईमानी या मूर्खता की वजह से कारखाना फेल हो जाए तो। मेरा तो करोड़ों रुपए का कर्जा भी माफ हो जाएगा और मुझे और रुपया देगी सरकार, वह कारखाना चलाने के लिए लेकिन किसान की जमीन बिक जाए तो कोई रास्ता बताओ कि किसान कौन से कुएं में जाकर गिरे। क्या किसान की जमीन की नीलामी के बाद आप उसे जमीन देंगे काश्त करने के लिए? इससे बड़ा कानून कौन सा हो सकता है?

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः अपने कथन की पुनरावृत्ति करना चाहता हूं कि यह जो उत्पीड़न आपकी सरकार ने इतने दिनों तक रखा हम उसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: आपकी सरकार कब तक दूर करेगी वह मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री सोमपाल: निश्चित रूप से दूर करेंगे। हमने कहा कि हम करने जा रहे हैं।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: क्या आप किसानों की जमीन को बिकने नहीं देंगे बैंकों द्वारा?

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है उस दिन।

SHRI SOMPAL: The chronic problem with all these former rulers is that they discover the wisdom at a very late stage when they are not to tackle the problem. But we will surely....

SHRI S.S. SURJEWALA: What about the present people? I want to know from this Government.

SHRI SOMPAL: This is a belated discovery of wisdom on the part of Congressmen. But we would look into this.

जहां तक इन्होंने बाजारों की बात कही है, यह बात सही है। इसमें भी इनका कथन है। उन्होंने कहा कि विश्व बाजार से जोड़ेंगे 21वीं सदी में जा रहे हैं। यह बात सब जानते हैं कि 40 प्रतिशत जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वह हमारे आंतरिक बाजार से तो जुड़े नहीं, यह चल दिए ये विश्व बाजार से जोड़ने। हम उनको जोड़ेंगे तब बाद की बात करेंगे और ग्रामीण विपणन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करेंगे निश्चित रूप से। इसी सदन में आपके समक्ष माननीय सुरजेवाला, जब हमारे पूर्ववर्ती माननीय डा॰ जाखड़ कृषि मंत्री थे, आपके सामने हमने यह सवाल पूछा था कि दिल्ली में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट आज तक भी लागू नहीं किया जाता। वहां आज भी हाथ के ऊपर रुमाल रखकर बोली होती है। कुछ नहीं किया था उस सरकार ने। हम निश्चित रूप से इसमें ठोस कदम उठाएंगे। ...(व्यवधान) करेंगे, थोड़ा सा सांस आने दीजिए। अभी आप लोग भी तो दुखी करते हैं। ...(व्यवधान) आप भी तो लोगों को उकसाते रहते हैं। कुछ समय दीजिए सोचने का।

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः** समय बहुत कम है आप लोगों के पास।

**श्री सोमपालः** समय कम नहीं है, हम कम समय में काफी काम करेंगे।

जहां तक मंडियों का विकास है, मैंने बात कही है कि मंडियों के विकास का एक कार्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसके परिणाम आप शीघ्र ही देखने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चौधरी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण बिन्दु सदन के सामने रखे और मुझे भी उनका उत्तर देने का अवसर दिया।

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः** मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** आप बैठिए न, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलेंगे न।

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः** मैं आज जाने लग रहा हूं। मेरे सारे साथी इस सदन में रहे हैं या आज हैं और सभापति, उपसभापति और आप जो हैं, यहां का स्टाफ जो है मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं। अब की बार मैं नहीं आऊंगा, 3-4 दिन बाहर हूं। मैं विदाई ले रहा हूं एक तरह से इस सदन से। मुझको बहुत खुशी है कि मैं यहां से जा रहा हूं। लोगों को दुख होता है मुझे दुख नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि मैं हमेशा ...(**व्यवधान**)

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** आप बैठिए न, हम आपको फेयरवैल देंगे, थोड़ा बैठिए न आप, प्लीज बैठिए।

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः** मैं जाने लग रहा हूं मेरा फेयरवैल कब देंगे?

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** सब मेंबर देंगे, आप थोड़ा बैठिए न प्लीज।

**श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान):** सर, मैं दो विद्वान चौधरियों के प्रश्न और उत्तर के बाद मैं गांव का एक आदमी प्राकृतिक आपदा के बारे में ...(**व्यवधान**)

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए।

**श्री ओंकार सिंह लखावतः** मैं प्राकृतिक आपदा के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, एक जो सबसे बड़ी विपदा इन दिनों जो सारे विश्व को तो परेशान कर रही है, पर भारत को भी कर रही है और मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान उस ओर बड़ी गहनता से आकर्षित हो। यह समस्या है अलनिनो की जिसकी वजह से अलनिनो के कारण और लानीना के कारण पिछले 1901 से लेकर 1996 तक 17 घटनाएं तो अब तक हो गईं। यह शब्द बड़ा वैसा लगता है, प्राकृतिक आपदा में यह शब्द कहां से आ गया और इसलिए मैं सदन का ध्यान मिलान कोविच साईकिल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन्होंने कहा है कि—He declared that three basic variations in the earth's movement affect the global climate. A one-lakh-year cycle in the planet's orbit, a forty-one-thousand year cycle in the tilt of the earth's axis and a twenty-three-thousand-year cycle in the wobble of the axis'.

महोदय, यह बड़ी गंभीर समस्या है। प्राकृतिक आपदा को केवल सामान्य चर्चा करके नहीं समझा जा सकता। इसलिए मैं आपका ध्यान मैडेलीन नेश की एक ऑब्जूरवेशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे कहते हैं कि—

> "But as bad as the past year has been, the future may hold no relief. The period following El Nino often brings a cooling of those same Pacific seas—a climatic pattern known as La Nina, which generally produces sharp reversals of whether patterns around the globe. Some scientists now say 1998 could witness an unusally strong La Nina, and Asia is bracing for its onslught."

महोदय, हाल ही में भारत के अंदर भी इस बारे में जो कुछ कहा गया है, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत बड़े संकट की चेतावनी है।

> Shri P. Shekhar has quoted: "The list of cases against global warming and El Nino is growing. Apart from the forest fires that raged Australia, Americas and Indonesia; drought world-wide; and the excessive heat in our country this summer, they are now being implicated in an unprecedented bleaching of coral reefs along with the south Asian coasts, wiping out the entire marine

fauna in certain hot spots in the Indian Ocean and the adjoining seas."

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार से जानना चाहता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा के जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार की तैयारी क्या है? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 1996-97 वर्ष को अगर हम ले लें तो 241 जिले प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए, 52523 गांव प्रभावित हुए, 42.27 लाख हैक्टेयर भूमि इससे प्रभावित हुई, 3 करोड़ 68 लाख जनसंख्या इससे प्रभावित हुई और 24 लाख हैक्टेयर भूमि में उगी फसल को नुकसान पहुंचा, 1560 व्यक्ति मरे हैं और 24,850 पशु मारे गए लेकिन इसके विपरीत वर्ष 1997-98 में 488 जिलों में से 389 जिले प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए, 77025 गांव प्रभावित हुए 171.55 लाख हैक्टेयर की काश्त प्रभावित हुई जिससे 4.75 करोड़ लोग प्रभावित हुए 153.74 लाख हैक्टेयर भूमि की फसल समाप्त हो गई।

महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष में 2,373 व्यक्ति मारे गए हैं और 28,000 से अधिक पशु मारे गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ रुपये की राशि के आसपास की मदद भारत सरकार ने देने का फैसला किया है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारी आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष है। आजादी के इन 50 सालों के दौरान कितने लाख लोग प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए, कितना हमारा नुकसान हुआ जिसको आंका नहीं जा सकता है, कितनी हमारी भूमि खराब हो गई, कितने पशु मारे गए, कितने व्यक्ति मारे गए, कितने खरबों रुपए की फसल समाप्त हो गई, इसकी जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि इन 50 सालों के अंदर कितना रुपया प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च हुआ और कितनी उनको राहत मिली।

महोदय, अब मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं और वह प्रश्न यह है कि बाढ़ आती है क्योंकि सरप्लस पानी है। बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि पानी का जो चैनल है, उससे अतिरिक्त पानी है और दूसरी ओर हमारे देश में 60,000 करोड़ रुपए का सिंचाई पोटेंशियल बेकार पड़ा हुआ है, 14 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का पानी बेकार पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ 70 प्रतिशत किसानों के खेतों के लिए पानी नहीं है। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन 70 प्रतिशत किसानों के खेतों को पानी देगी? जो सरप्लस पानी बाढ़ का आता है, जिसको आप नियोजित नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 50 सालों में उसका नियोजन नहीं हुआ है, क्या ऐसे 70 प्रतिशत किसानों के खेतों को पानी देने की सरकार की मंशा है?

महोदय, मेरा अगला प्रश्न यह है कि इस प्राकृतिक आपदा को क्या राष्ट्रीय समस्या घोषित करके एक अलग से विभाग बनाकर सुबह और शाम, दिन और प्रतिदिन पूरे वर्ष केवल प्राकृतिक आपदा से बचाव और निदान सोचने के लिए, सरकार कुछ गंभीर तरीके से विचार करने के लिए तैयार है? सिर्फ यूरिया बांटने से और टीन-शेड देने से और दवाओं के पैकेट बांटने से प्राकृतिक आपदा का निदान नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ कारगर कदम उठाने की सरकार की मंशा है क्या? महोदय, इस अतिरिक्त पानी के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया है।

महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि जितनी भी हमारी मौसम विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं, जितने भी वैज्ञानिक तौर-तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको कारगर और परिणामजनक बनाने की दृष्टि से सरकार की इच्छा शक्ति क्या है? ये मेरे कुछ प्रश्न हैं जो प्राकृतिक आपदा के बारे में मेरी सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। मैं मंत्री जी से इनका जवाब चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, at the outset I would like to submit that our notice for the Calling Attention was specifically on the heat-wave in Orissa. Maybe for the convenience of the Secretariat, they have amalgamated it and included in this Half-an-Hour discussion. But, Sir, I do not know whether the Hon. Minister, who is present here, has got enough data to give answer to our questions.

Sir, the natural calamity, which we are discussing today, is a very very important issue. As an hon. Minister has mentioned here, taking an excuse under the natural calamity will not be a proper appreciation of the problem. I must emphatically say what the natural calamity is. It may be a flood, a cyclone, an earthquake, a tornado, a heatwave. For all natural calamities, as the hon. Member was

saying just now, there is a solution. The solution is that the surplus water of the river can be checked by embankments and diverted through channels for irrigation purposes in other areas. That way the flood can be checked and its water put to a better use. About the cyclone, tornado and earthquake also, a prior information can be obtained and given to the public for their protection. About the heat-wave also, the same thing can be done. So, just by saying that this is a natural calamity and the Government cannot do anything will not be a correct appreciation of the problem, especially in this age when this Government is thinking of having internet connections or setting up STD booths all over the country and is also having some new ideas in different directions. We must also think on this very seriously, because it is a very serious problem for the country.

Sir, I do not know what was the position fifty years ago and what would be the position fifty years hence, but, we know that the life expectency in our country fifty years ago was around 45 years and today it is above 70 years. This life expectency has been inceasing gradually because of better living conditions and health consciousness. But, Sir, what was there 50 years ago and what will happen 50 years hence cannot be compared. Since this aspect of natural calamity is a very serious one, I would like to know whether the Central Government would consider having a separate department to deal with the problem and to provide relief to the people in a better way.

Now, I come to the relief operations to the people affected by natural calamities. Sir, the State of Orissa has quite often been affected by cyclones, floods, tornados and heatwaves. I am sorry to say that the affected people of my State have also been neglected by the Government of India and are discriminated against, be it the case of crop loss, life loss, house loss or any other loss. The relief given has always been comparatively less. I give you an example: Rs. 10,000 was given to the next of kin of each of the victims of the heatwave by the State Government in Orissa, but Rupees one lakh as relief was announced for the next of kin of each of the victims of the bomb blast that occurred in Delhi on 26th of this month. We are very happy about it. We would have been more happy if that amount of Rs. 2 lakhs had been given to the family of the person who died on account of heat wave in Orissa. In our State, some persons have died due to natural calamities. It may be due to heat wave, or it may be due to cyclone. It may be due to floods. It may be due to earthquake. It may be due to bomb blasts. A person might have died in Kalahandi Jogpur, Cuttak, Sambalpur, Jharsuguda Koraput in Orissa State. He migh have died in Haryana or Jammu and Kashmir. He might have died in Kanyakumari or Assam, Meghalaya or Manipur. That does not make any difference. The person who has been killed due to heat wave in Orissa has left his family behind, a girl to be married and a school-going boy a bed ridden mother. They have the same difficulty and the same needs as others are having. After his death nobody is there to help them. Therefore, the Government should help them. Should there be a different type of compensation paid to the family members of the deceased persons who have died in Kalahandi, Sambalpur and Koraput of Orissa State? Here each family would get Rs. 10,000/- as compensation, whereas the family of each deceased person who has been killed in Haryana or Jammu and Kashmir or any part of the country will get Rs. 1 lakh. It is justice? It is not justice. Take the case of people affected by cyclones or floods. Sometimes the Prime Minister is also giving money from the Prime Minister's Relief Fund. But in the case of people in Orissa who died due to heat wave compensation is given from the Prime Minister's Relief Fund. I would like to

give a detailed information about the heat wave in Orissa. An unprecedented heat wave swept across the State from the last week of May in the western districts of Orissa. The maximum day temperature was reported to be in the range of 45°C during the last few days. The maximum temperature reported in the State from 24.5.1998 was 47°C in Sambalpur and 48°C in Jharsuguda. It was 48°C in Thilagarh and on 28.5.1998 it shot up to 50°C in Tillagarh.

After this heat wave, a report was received from the Director. Meteorological Centre, Bhubaneswar. It says that the primary reason for the prevailing heat wave is the weakening of southerly and south-easterly winds which eluded the State. Ultimately, the Government report is because of this unprecedented heat wave 2,042 persons have died due to sunstroke. The Government has received this report from District Collectors.

The other day when I put a supplementary on Question No. 325, the hon. Minister replied, "We don't have the report." When I was telling the truth, many Members did not believe me. But the Government report says 2,042 persons have died due to the heat wave. I know and I can say emphatically that the number of deaths due to heat wave in Orissa was 4,000. This is unnatural. This is unprecedented. I think this is a very, very serious thing.

The Government's figure of 2,042 deaths does not include the persons who died in remote areas of our State. That report has not yet reached the Government. In many parts of the State, many people died, and their relatives creamated their bodies. They did not obtain the post-mortem report, doctors' certificate. The Government is not prepared to believe them because they could not get the post-mortem report, doctor's certificate. You know the attitude of bureaucratic system. Sometimes even if a person died in the heat wave, the Government was not prepared to accept it because there was no dcotor's certificate.

My submission is when 4,000 persons died due to heat wave in Orissa, so far the Prime Minister has not visited our State. Till today no Central team has visited Orissa to inquire how 4,000 people died. Mr. Vice-Chairman , Sir, Orissa is also a part of this country. Is it not a serious incident? The other day the Minister has told us in this House that he has not received the report from the State Government. I am sure, the State Government has sent the report. Even if the State Government has not sent the report, the Central Government should have called for a report from the State Government. They have all the sources to get the information. About 4,000 persons have died due to the heat wave. It it not a serious thing? Sometimes the Central Government is deputing Central teams to States to study the law and order situation for some political reasons. I do not blame this Government. In the past, many Government did the same thing. When 4,000 persons died due to heat wave, was it not the duty of the Prime Minister to visit Orissa State? Is it not the duty of any Central Minister to visit Orissa and find out as to how 4,000 people died? This is a serious situation which has been created. Many people in Orissa are afraid as to what would happen tomorrow, as to what would happen next year. In 1996 the temperature was 46°C. In 1998 the temperature was in the range of 48°C to 50° and 4,000 people died. Who knows next year the temperature may shoot up to 55°C and more than 10,000 people may die and everbody will sit quiet. I want to bring to your kind atention the fact that this is a very serious thing. I want to know specifically from the Government why it is happening in Orissa. Orissa is a place where the temperature never goes up beyond 42-43 degrees celcius. Why has it gone up to 48-50 degrees? Is it because of the test done in Chandipur? Or is it because of the nuclear explosion which has been done in

Pokhran last time? Or is it because of some other reasons? That is to be investigated. The inhabitants of Orissa are now apprehensive of the future. They are afraid as to what is going to happen. This is a serious situation created in Orissa and it has been neglected by the Central Governemnt They have given only Rs. 10,000 as compensation. If a cyclone victim or other victims could get Rs. One lakh or Rs. 2 lakhs, why the victim who died in Orissa in the heat wave or his family should not get that amount? The second aspect in regard to compensation is, the Orissa Governemnt is saying that for death in a heat wave, as per the relief rules, the relief that could be got is only this much and nothing more. They have said so. I do not know whether the State Government is competent to say this or the Central Government. Even if the rule is so, it should be immediately amended and the amount should be enhanced. A heat-wave death is also death. Whether it is a heat wave or flood or cyclone or militant action, the persons killed is killed and the family suffers. There is nobody to help the family.

In this critical situation, I want to submit that this is an unusual incident. Orissa is very, very peaceful normally. Orissa has mineral resources. We have the longest coastal line. We have iron, we have coal, we have forests. But Orissa has always been neglected by the Central Government. In this case also, in this heat-wave incident also, Orissa has been thoroughly neglected. The people of Orissa have been neglected. I want to give certain suggestions to the Government which they may examine.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTAN BISI): No. Please don't do that. Kindly conclude.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: When so many people have been killed in the heat wave, the Prime Minister and the Ministers concerned should visit Orissa immediately. The Central Government should send Central teams to understand the cause of the heat-wave condition. It should pass an order for payment of a minimum of Rs. One lakh as *exgratia* payment to the next of kin of the deceased persons. There should also be a thorough investigation as to the cause of the heat wave. The Government of India....

THE VICE-CHAIRMAN SHRI SANATAN BISI: These points have already been covered.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: I want to emphatically say that in Rajasthan and Orissa where the test and nuclear explosion have been done....

THE VICE-CHAIRMAN SHRI SANATAN BISI: These points are already there.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: It has been done in the interest of the nation. Something is done in the interest of the nation and the people of the State have accepted it because it is in the interest of the nation. The nation also should express concern and find out if there is any difficulty arising out of this experiment; and if there is any difficulty, necessary steps should be taken for the protection of the inhabitants of the State. Thank you.

SHRI RANGANATH MISRA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would only add some points on the same issue. Whether it is 2,000 as stated by the state Govt. or 4,000, as reported in the press, a lot of people have died and it is an unusual event. Normally, some people die in the western Orissa side where the temperature goes up in summer. This time, it has been the coastal belt. The normal weather practice is, if we get a little high temperature consecutively for two or three days, we get a shower of rain which cools it down. Something has gone wrong. This has been very unusual. Is it because of the forest cover being reduced or is it for some special reason? This should be investigated. I would suggest that a Scientific Committee which would be appropriate for the purpose should be set up immediately. And they

should be asked to go and find out what exactly is the reason for this unusual behaviour so that we can learn a lesson from that for future. If it is delayed, then we may not have the basic material available for doing research.

The second thing is, I join my learned colleague in the Stand, that compensation should be provided. It is a natural calamity. It is being looked after by the Rehabilitation Department. The people are very poor and most of the people who have died are the lowest of the low. Orissa, as such, is a poor State and the people who have died are really the poor ones. Therefore, immediate action should be taken. I also join my learned colleague because the relief code does not permit a compensation of more than Rs. 10,000/- to be paid. That is how the Orissa Government has not come forward with more than Rs. 10,000/- If this is the rule which stands in the way, the rule should be overridden. If it is not the rule, compensation on a normal basis or on a comparative basis should be given. Whether it is one lakh or two lakhs, that is not the question. The question is of rehabilitation. Rehabilitation need not be only in terms of money, rehabilitation can come forward also in other ways. A scheme for rehabilitation in the case of those who have died this unnatural death should really be evolved immediately. I know the people have died in their own houses and not on the roads. It is on account of the fact that the Nature was very callous, cruel probably to them this year. These are the things which I suggest, but I request that immediate action is taken.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the intensity of the adverse effects of the natural calamity is increasing year by year, season by season. My friends from Orissa have just now brought to our notice this important aspect. That is not a case with regard to Orissa alone. If you look at the adverse effects of the natural calamity, the intensity is increasing year by year. There may be many reasons for it. One is every natural calamity is making its imprint on ecology. There would be a permanent damage. If we do not remedy it, certainly the next natural calamity's adverse effects will be more intensive. The second is there is already a decline in public investments, particularly in certain areas. This is also a factor intensifying the adverse effects. The third is some of the projects that we have got have many defects; I am not going into the details. So, I would like to know from the hon. Minister what steps the Government intends to take in this particular area for remedying the adverse effects on ecology, environment and also for conducting a scientific study on certain projects. Of course, many ideas are there; I am not going into the details. It is very late now. The second aspect is, for natural calamity there are two set-ups as per the recommendations of the Tenth Finance Commission. One is the Calamity Relief Fund. Another is the National Fund for Calamity Relief. The amounts are fixed from 1995 to 2000. What is the experience of the Government? According to my knowledge, these two set-ups are not sufficient to meet the present situation. Now the Eleventh Finance Commission has come into existence. I would like to know from the hon. Minister whether the Government will take the initiative to make changes in the terms of reference and look into this particular aspect. These two set-ups came into existence on the basis of the recommendations of the Tenth Finance Commission. Our experience is that these two set-ups are not sufficient to meet the situation and the severity of the natural calamities that occur in certain parts of the country. The third is that in 1989 the United Nations passed a resolution asking all member-countires to take steps for reducing the adverse effects of natural calamities. We all know that we cannot stop the impact of natural calamities. But we can take certain measures for reducing the adverse effects of natural calamities. As decided by the United Nations, this decade is

observed as a decade of reducing the adverse effects of natural calamities. Of course, the Agriculture Ministry has constituted some committees, held some seminars, brought our some pamphlets and posters, etc. But this is not what we require in the present situation. Many measures can be taken for reducing the adverse effects of natural calamities. I am not going into the proposals. Many proposals can be made. Two more years are there. Why can't the Government think of starting something for reducing the adverse effects of natural calamities? The fourth aspect is that now funds are distributed from the Prime Minister's Relief Fund to certain States. There are wide variations in the quantum of funds granted from the Prime Ministers' Relief Fund. I would like to know from the hon. Minister what the criterion is for granting funds from the Prime Minister's Relief Fund to the States. These are the four points to which I want a reply from the hon. Minister. Thank you.

DR. M.N. DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would not dare at this stage to test the patience of the remaining few Members of this august House, who are still good enough and kind enough to wait and listen to the speeches on natural calamities. I would not like to go into the details of what the natural calamaities are. I would like to simply refer to one warning given by the scientists and the environmentalists about the in-coming 21st century. The warning is that the departing 20th century is leaving for the in-coming 21st century one of the worst tragedies ever expected by man, that is, the real Nature will take revenue upon the human nature. The modern man, for his own selfish interest, has disfigured the Nature given by God or by the Creator. There are huge holes in the ozon layers; ultra violet rays are coming to harm the mankind; deserts are expanding; the heat is increasing; the snow is melting at the poles; the sea level is rising. A time may come when great cities like Tokyo, London, Copenhagen, our Andaman and Nicobar Islands, and many more places, will be drowned and submerged under the sea. But these are different stories altogether. I would like to refer particularly, not to natural calamities, but to a calamity which I consider as the most unnatural natural calamity, a calamity which is unnatural, uncommon, unusual, unprecedented, unknown and abnormal. What happened to Orissa this year? From May to June, in three to four weeks' time, Orissa was struck down by a natural phenomenon unknown to Orissa during the 3,000 years of its history. It was never known. There was heat wave and there were deaths due to sunstroke. Earlier hardly five or six persons used to die in a year due to heat. In Rajasthan and Uttar Pradesh the number used to be more than three digits. But what happened to Orissa this year? Mr. Vice-Chairman, Sir, you know that several districts of Orissa are situated on the Eastern seaboard facing the Bay of Bengal and having places of health resorts and summer resorts like Puri on the sea beach and Gopalpur on the sea, and the other half of Orissa is full of forest belts. Orissa enjoys a temperate climate. Orissa does not know either the heat or the winter or Delhi. That being so, What happened to Orissa this year? Why and what for was there this unusual phenomenon? Sir, I would like to draw the attention of the House and through you, the attention of the Government to one thing. Unless a team of experts, environmentalists and scientists, is sent to investigate into the cause of this unnatural phenomenon, there will be some other sequence or consequence. There is something called public perception or popular perception. I would say that popular perception may be purely hypothetical, totally unfounded and far from being based on truth. But unless the perception is corrected in time and contradicted by authorities, that perception will take the form of conviction. And what do the people say? Balasore never knew—I belong to Balasore district—we never knew about heat wave or deaths by sunstroke. The common people come to

us and ask, "When you go to Parliament, would you put a question to the Government? Was there a clandestine nuclear warhead or weapon experiment on Agni or Trishul or Prithvi or Akash from Chandipur on sea?" When I go back what answer could I give to them? Unless the Governemnt correct and contradict the popular speculation or imagination or just meaningless, unfounded suspicion, they are going to create a conviction in their mind that some new experiment had taken place; and there will be resentment and the resentment will lead to resistance against future missile tests. We are proud of Chandipur that it has found a place on the defence map of India. We are proud that in the whole of India and the sub-continent, you do not find a place like Chandipur-on-sea where for miles and miles together there is no high water and there is no high wave. The scientists conduct the experiment of ballistic missiles, medium range or long range. They conduct test fires. No other place on the Indian coast will give them such a spot. We are proud of Chandipur. At the same time, we must know from the scientists, those who experiment from Chandipur their medium range missiles, the truth of the fact. Let them categorically and emphatically say that this heat wave, these deaths due to sunstroke have no relation whatsoever with the missile tests. That is our duty, that is our responsibility. We are, after all, patriots and we must convince our people that they should not go by calculations and speculations or by rumours or by blind belief. We can tell the people that the heat wave was due to other natural factors, like deforestation, and general rise in temperature all over the country. There are many other factors also. We may explain it to the people. Unless the Government itself is convince by expert knowledge and investigation and unless the Government gives a catagorical statement, how can we face the people? So, my humble submission to the Government is that without any further delay kindly send a team of scientists, including some of those scientists who are connected with these tests at the Chandipur-on-sea. Once we get their assurance, we will ascribe the heat wave to nature. Let Nature take revenge on us if we have deforested our country, if we have created sand ridges on the sea-bed by deforestation. Many factors may be there for the heat wave. But at this stage we submit that the Government should come forward with a categorical assurance and commitment that the heat wave was in no way related to missile tests at Chandipur in Orissa.

SHRI O.S. MANIAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, natural calamities have become almost a regular phenomenon in our country. One or the other State is hit regularly by either floods, heavy rains, storms, famine or a natural calamity. Whenever a State or region is hit by a natural calamity, it takes several days for the Centre to assist the State Government in providing relief. The Calamity Relief Fund is so limited that the States are not able to meet the requirements. Funds from the Centre for calamity relief are released only if the calamities are of rare severity. To assess this, the Centre takes many days, even more than a week.

I wish to impress upon the hon. Minister one point. If calamity relief is not provided instantly, the delay even leads to loss of precious human lives. In Tamil Nadu, the coastal districts of Nagapattinam, Cuddalore and the other coastal districts are affected by floods and storms every year. Farmers, fishermen and poor people living in coastal areas are the worst affected. They all loose their livelihood. Natural calamities dispossess them of all their belongings and they depend only on what the Government provides. Therefore, I appeal to the hon. Minister to see to it that the Central team reaches the affected areas for an assessment immediately or at least the next day. The

relief fund should also be released at once, without any delay.

I have a suggestion regarding the relief fund. Since natural calamities are recurring every year, it would be proper to provide for funds for calamity relief in the Five Year Plan itself because when there is a natural calamity in a region, all our plans are upset. The standing crops perish, infrastructure like roads, etc. is damaged and life comes to a standstill. based on the past experience, funds could be provided in the plan itself for calamity relief State-wise. The NFCR could be used in case the need is more. This will enable the State Government to provide immediate relief.

Sir, the amount of Rs. 13 crores which was due to be given to Tamil Nadu for 1996-97 towards crop insurance, has not been given so far. The farmers are suffering. I request the Government to release this fund immediately.

In Tamil Nadu, the farmers of coastal districts are hit by floods and storms and the farmers of water-starved districts like Ramanathapuram are hit by famine. The crops are either damaged by floods and storms or they dry up due to failure of monsoons. The farmers must be given crop insurance so as to save them from indebtedness. This year only Rs. 100 crores have been allocated for the Crop Insurance Scheme to be launched only in 24 districts in the entire country. This is not enough. I request the hon. Minister to convince the Finance Minister to allocate more funds so as to include all the worst affected districts of Tamil Nadu in the Crop Insurance Scheme.

I am very happy to say that the hon. Minister of Agriculture, Shri Sompalji, has always been fighting for the cause of agriculturists. For the past two years, due to natural calamities in the entire Cauvery delta are in Tamil Nadu, the agriculturists have been affected by heavey rains. They are not able to repay their loans which were given to them by cooperative and national banks. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any proposal to waive these loans of agriculturists or whether any instructions have been given to the State Government to waive loans of affected agriculturists.

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, we have discussed about natural calamities many times in this House. The most common natural calamity which affects all the States of the country is flood. It is followed by cyclone, drought, heat wave, earthquake and landslide. Sir, the procedure which has been formulated by the 10th Finance Commission for allocating funds from the National Calamity Relief Fund needs to be reviewed because on the basis of population some amount has been earmarked for every State, irrespective of the damage or extent of calamity which is being faced by a paticular State. In certain States, a few phenomena like floods are of recurring nature. For example, in Assam there was a big earthquake in the year 1950. As a result of that, the depth of the river Barahmaputra had increased greately. Since then, flood is a regular phenomenon in Assam and the annual loss due to flood amounts to Rs. 3,000 crores. The cumulative loss till today would be around Rs. 1,25,000 crores. If we also calculate the money invested in repairs of roads or clearing damages or giving relief and rehabilitation to the people, the loss will be much more. Sir, if we cannot take steps for permanent solution, then these temporary and ad-hoc measures will never help the country in over coming this situation. The Constituion has provided that every State Government is responsible for relief and rehabilitation and maintenance of law and order. While miseries from water, from air i.e. cyclone or heat wave and drought are to be dealth with by the State Governments, the revenue from assets like minerals, petroleum, coal, etc., belongs to the Centre. We are just

trying to push the States towards financial bankruptcy. Not to speak of repair works or giving relief and rehabilitation to the people, the State Governments are unable to pay salaries to their employees. Along with these problems, the problem of finsurgency has cropped up. They are finding it difficult to control insurgency problems. The State Governments are finding it very difficult to help the people in natural calamities because they don't have fund. Sir, this is the time when we must formulate some permanent solution to this flood problem.

Sir, I hail from the State of Assam. The situation in Assam is that there was a proposal with the Central Government for controlling the rivers in the State. For this purpose, many commissions were appointed, the Brahmaputra Board was constituted in order to have a master plan for the river system, but till today no river has been controlled. The situation is being aggravated year after year. This year, the extent of flood is such that out of 23 districts in Assam, 20 districts have been affected by flood. Earlier flood water used to recede within a week or ten days. But, this year flood water is continuously there for the last two months. This has been affecting the entire area. The hon. Minister of agriculture, Sompalji has very kindly visited that area. he has a personal assessment of the extent of damage. Some of the areas are inaccessible for the last one month. The entire State is delinked from road, rail and other means of communication for the last three days. What will be the consequences? When this flood water receds, there will be no cultivation and no agricultural cropping. Whatever was left with the people has already been lost. There is no road link. I do not know what the people will do. I do not know how the people there would have their livelihood, their earnings and fulfil their requirements. So, this is a very peculiar situation which cannot be compared to normal floods coming elsewhere in the country. I must support the feelings and anguish expressed by the hon. Members from Orissa. In certain areas of the country whenever there is a natural calamity high ups from New Delhi would always fly there and declare some amount without any assessment. But, for a State like Assam, they wait for a Central team to visit and make an assessment to give a report. But, by that time people suffer more. At least, some funds can be released from the National Calamity Relief Fund in advance to meet the situation. For those areas where floods are continuous there should be a special fund ....*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please conclude.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Sir, the Tenth Finance Commission earmarked the allocation on the basis of pupulation which is not just and proper ....*(Interruptions)*.... Sir, I would like to inform the hon. Minister that the economic situation of the State is very bad and the State Government is unable to help the people and rescue the people from the miseries. ....*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI SANATAN BISI): You have already stated this point.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Sir, I would like to submit one more point with regard to security-related expenses. Sir, our State has no money. Our developmental money has been diverted, for security-related requirements though this is the responsibility of the Central Government under article 355. Now, the money has not been reimbursed by the Centre. I do not know how the State Government will deal with this situation. This is a very peculiar situation. Sir, here my another suggestion is that we can take help from the foreign funding agencies to solve this problem of floods and for controlling the river system on a permanent basis. ....*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI SANATAN BISI): Please conclude.

DR. ARUN KUMAR SARMA: We have always been told that there is a dearth of money for a permanent solution of this problem. Sir, a dam was proposed on river Subansiri. The original cost of the project was Rs. 3500 crores. But, now this has esclated to Rs. 12,000 crores. Now we do not have money. We must get loan from other agencies and have a permanent solution of this problem. If we are able to do that, we will be able to save from Rs. 4000 to Rs. 5000 crores every year. In this way we will be able to compensate this expenditure within three or four years. I do not know as to why the planners do not visualise this kind of a proposition to have a permanent solution of this problem which is of a recurring nature. Sir, now, the States are responsible for increasing the production. We are always blaming the State Government. If we cannot help the States to have infrastructure for more production and only burden the States, then I do not know how the expected production will be coming and how we will be able to compete with the rest of the world. It will not be possible. ....*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please conclude. ....*(Interruptions)*....

DR. ARUN KUMAR SARMA: Sir, with these words, I conclude. Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, fortunately or unfortunately, eventhough the subjects we are dealing with are important, we are taking up the most important issues only during late hours.

When we are talking about natural calamities, it is altogether a different connotation for Indians because in the USA only 2% of the people are engaged in agriculture; in the Western Europe 5% of the population is engaged in agriculture and the Eastern Europe it is 22%...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Why are you going to those places? You confine yourself to India.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, in India, more than 72% of the people's main livelihood is agriculture. At the same time, 70% of their income on agriculture goes to fill up their basic needs. In urban areas it is 60% and in the rural areas 70% of their income goes to meet their basic needs. The hon. Minister, while he was talking about the interest rates, said that inflation has gone up to 8%. In case you want to reduce inflation, we must see that our savings are more. To have more savings, we have to take more care of agriculture. And, unless our savings reach more than 30%, we cannot invest on industry.

Coming to the subejct, what I would like to say is, the hon. Minister should know and understand the difficulty we are experiencing in the States. For example, in Tamil Nadu, in 1996, for natural calamity due to floods, we had given a compensation to the tune of Rs. 55 crores. Sir, more than ten lakh people were affected. In 1997, Rs. 59 crores was allocated and the same had been given to the agriculturists. In both the years *i.e.*, 1996 and 1997, we had spent more than Rs. 114 crores. I already said in this august House that as far as the States are concerned, we are having inelastic income. We cannot increase our income. That is the situation. Due to floods, another situation had arisen. Last year and this year, to mitigate the situation and to lessen the burden due to desilting of canals as well as some tanks, we have spent more than Rs. 32 crores. Last year we had spent Rs. 10 crores for canals and this year we are spending Rs. 20 crores.

Sir, we are also giving pension to aged agriculturists. We are giving Rs. 150 pm per head. Why I am telling all these things is, the Central Government should know the difficulties, and see how the

State Governments are suffering because of these factors. Sir, this year, due to waiver of land tax...*(Interruptions)*...We had waived more than Rs. 43 crores on land tax. We have said that suppose if anybody already paid the tax, the same will be adjusted in the next season. Apart from that, we have also waived penal interest this year to the tune of Rs. 50 crores. Sir, waiver of penal interest as well as land tax comes to Rs. 93 crores. This is the situation in our State. This year there has been plenty of production in paddy and for that we have created more than 900 purchasing centres and through these centres we have purchased 18 lakh tonnes of paddy for that we have to invest money. Our problem is that you have fixed the price for paddy, but the people are asking for more, and that too with retrospective effect. We have agreed to their demands and have given them Rs. 35/- more than what the Central Government had fixed, with retrospective effect. For sugarcane they have asked for Rs. 1000/- per tonne, and the Central Government had fixed Rs. 484.50 per tonne. So, a meeting was convened between the representatives of sugarcane growers and the Government officials, and the Minister. In this meeting we came to a conclusion and reached an agreement by which we have agreed to pay them between Rs. 695 and Rs. 881 per tonne. We are being confronted with this problem. Everybody knows that people are suffering due to natural calamities like flood, cyclone, etc. We have to seek some remedy for that. I share the sentiments expressed by the Members hailing from Orissa. I understand the reason expressed by Shri S. Ramachandran Pillai. I would like to know about the crop insurance. Sir, yesterday when we were talking about the Non-banking Finance Companies, I had asked for insurance for the entire loss incurred by the farmers. At present, the crop insurance scheme is confined only to the loan amount. So, we demand from the Government, we demand from hon. Minister that the crop insurance should be for the entire loss incurred by the farmers. But, now you are giving insurance only for the loan amount, which the agricultrists are getting from Cooperative Banks and other Institutions. I would like to know what the Government is going to do in this regard. With these words, I conclude, Sir. Thank you.

**श्री सोमपाल:** उपसभाध्यक्ष जी, माननीय श्री लखावत जी ने अपने वक्तव्य में अलनिनो और लानीनो जैसी प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में चर्चा की है। एक तरफ अलनिनो का जाता है इसके कारण अति ऊष्मीकरण हो रहा है, दूसरी तरफ इसके विपरीत....

SHRI. S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Can you speak in English?

SHRI SOMPAL: I think, interpretation facility is there.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: It is just a request.

SHRI SOMPAL: Okay, I am switching over to English. He has mentioned about El Nino and La Nena. On the one hand, there is an apprehension that because of El Nino greater heat will discend on the earth, and on the other hand, La Nena would tend to cooling of the earth or, maybe, the other way round, I am not a scientist. I am just explaining what he has said. But, these are all beyond the control of human beings, and whatever the development of technology may be, I do not think it is possible to control, at least for the time being, such thins. But, the fact remains that there is a need to get sensitized about these things, and if any preparedness can be undertaken, it should be. There is an acute difference of opinion between the natural calamities' observers and scientists on these phenomenon. There are widely divergent opinions and assessments on the impact thereof. He has asked for the statistics for the last fifty years regarding the loss and damage due to these various natural calamities, which is not immediately available. But, there have been losses, and we do have statistics for the last few years, they are really frightening. So far

as this point on the flood damage is concerned, it is well taken. Recently, as Dr. Sarma said, we had an occasion to visit the North-East, and we have seen that really devastating floods are ravaging the whole of North-East since June last.

I have personally flown over the areas of Assam and Arunachal Pradesh and it is really a very heart-rending scene. I have never seen such a vast areas submerged in floods. I think more than a million people are submerged in the floods in Assam alone. Both in the North-East and Assam large landslides have taken place; avalanches have been there. We have seen cattle huddled on a small piece of land, water everywhere all-round for several hundred kilometres in Subanseri Division, North Lakhimpur, Jorhat and other places. It is very difficult and I was informed by the sea authorities that in the past 30 years such a flood has not been witnessed in Assam.

In Arunachal Pradesh, they said that in the past 30 years rains have never been so continuous and torrential as this year. It is raining there since May last.

Mr. Lakhawat wanted to know that we are doing to meet the water requirement and what we are doing in the matter of water management. *(Interruptions)* Yes, about surplus water. He is right that out of whatever rain precipitation takes place over the Indian sub-continent during the year, 4000 billion cubic metres, and in the monsoon, that is, seasonal rain 3000 million cubic metres, only 17.25 per cent of this water is utilized. And in the river flow, out of the utilizable flow only 37 per cent is utilized. Therefore, there is a lot of scope for utilizing water on a larger scale to the benefit of the farmers, for drinking water and for meeting other needs like the need for water in industries. We are embarking on a 25-year plan of Water-Shed Management in which we have water harvesting as the major component and thrust area. And to harvest water, store it over the surface, under the surface, underground water and managing it properly on a more economic and judicious basis with the latest techniques of irrigation and other things and keeping water clean and not allowing it to the polluted so that enough water is available for use as drinking water and irrigation water.

So far as the suggestion of coming out with devices and measures to mitigate the damage is concerned, I stated on several occasions earlier and I state it today also, surely it is needed and it is always being done. And there is a need for coming out with measures, that are emergent measures to meet the situation, short-term measures, medium-term and long-term measures for flood-proofing and other things. To mitigate the misery, fore-warning systems and communications systems etc. in case of floods razing the villages and informing the people and asking them to change the cropping pattern and habitation and identifying the flood-proofing zones, that is, flood-zoning through a legislation. The Central Government has already advised all the State Governments, but unfortunately, there has been no response from the States. They should come out with flood-zoning systems and prohibit people form inhabniting such areas which are usually prone to floods. *(Interruptions)*

On the points raised by the two hon. Members from Orissa regarding the heat-wave, we have never said that we do not have information. What we said earlier was that there is no formal memorandum seeking Central assistance from Orissa. So, I should put the record straight. Whatever information we have is this: the Government of Orissa has reported that several heatwave conditions prevailed in Sambalpur, Jarsuguda and Nalgore districts in the last week of May, 1998 resulting in the death of 733 persons due to sunstroke and hospitalisation of 1,224 persons in 25 out of 30 districts of this State. The State Government nas also reported that they have released Rs. 50 lakhs for

payment of *ex grana* assistance and issued instructions to the District Collectors to provide *ex gratia* assistance of Rs. 10,000/- to each of the bereaved families. Therefore, there are reports. It is a long report. I can provide it to the Members. But they have not sought any assistance from the NFCR. No memorandum has been received so far. In the absence of any memorandum, it cannot be given.

Shri Ramachandra Khuntia and Dr. M.N. Das from Orissa suggested that there should be a scientific and comprehensive study to find out as to on what account this extraordinary heat wave had taken place. But, according to the information available with us, there have been incidents of higher temperature recorded earlier. For example, in 1972, in Bhubaneswar, the temperature had gone up to 46.5° C. Bhubaneswar again, in 1967, recorded a temperature of 46.5° C. Cuttack recorded a temperature of 47.7° C. in 1957. On 6th March, 1948, 47.2° C. was recorded in Cuttack. I think this is an unbeaten record. But I agree that the loss of life is unprecedented. Maybe, with the increase in population, exposure has increased. Then deforestation has taken place. All these things have to be studied systematically. Surely, this point is very important and this must be looked into.

Shri Ranganath Misra—he has gone—wanted to know about the reasons and the factors responsible for these things and about compensation. They are already being reviewed. A Committee has already been set up.

Shri Ramachandran Pillai wanted to know about the adverse impact of environmental degradated and the remedy thereof. The natural remedy lies in conserving the environment and in rejuvenating the environment, for which so many schemes are going on. It goes without saying.

CRF and NFCR for providing higher relief is already under review. The Eleventh Finance Commission is seized of the matter. We have tried to underline the need for propagating the programme which was desired through the UN Resolution in Okahama in 1994. It has been declared as the Decade of Disaster Management and Reduction. We are taking adequate steps through organising seminars, disseminating information and working out codes to meet such calamities in a more better way.

Shri O.S. Manian asked about crop insurance and loan waiver. I had already informed both the Houses on an earlier occasion that the Government had already taken a decision to come up with a modified crop insurance scheme which will cover all the crops, all the regions, all the farmers, irrespective of the landholding and irrespective of the money. But it will be based on the premium. A concessional premium would be worked out for the marginal, the small and the weak farmers, and on an actuarial basis for the others. The loanee component would be required to have compulsory insurance. For the others, it will be kept voluntary. This scheme is under formulation. We are thinking of having a separate set-up—a corporation—Agricultural Insurance Corporation—as a subsidiary of the GIC. This will meet the requirement.

Dr. Sarma spoke about the fragility of the Himalayan Region. It is understood. There is a continuous pressure on the south-west side and the theory, the tectonic theory, says that there was a tectonic movement and the India Plate collided with the Eurasia-China Plate. That is why it is said, some part is still going under the Himalayas and the hills are rising even now. Therefore, faults are created. After some time, when adjustments take place, earthquakes take place. One was cited—in 1951. It had caused the rise in the level of the Brahmaputra. There is always a contention about the advisability and the desirability of having huge water resources, in terms of dams. Ecologists

and environmentalists have been warning agains this. All these things have to be evaluated.

Taming of the rivers is not difficult. You have cited the case for two dams. We discussed this in Guwahati too. The estimated requirement of resources is Rs. 40,000 crores which is too huge. But, still, it is under consideration. The Brahamputra Board coming out with plans and schemes to utilise and tame the seventeen odd rivers which are tributaries of the Brahmaputra is already there. There is a Working Group in the Planning Commission and the concerned Ministries, which is working on it already. But when it can be done is a matter resources and time.

Shri Virumbi says that important things are discussed at late hours. He belongs to the category of late importance. He says that saving has to be high. This is an economic matter. But, in spite of so low incomes in Inida, it is a very heartening phenomenon that our propensity to save is quite high. Even now we are maintaining a saving rate of 25 to 27 per cent. If we can increase it by 3 to 4 per cent, achieving a growth rate of 10 to 11 per cent would be very easy. So, this point is very important, and we should somehow find the means to defer the consumptionist tendencies. That is the only way to enhance it. Controlling the inflation is one of these But, because of the acute poverty and all the needs waiting at that critical level, it makes very difficult to defer the needs because they are already so waiting. So, whenever income accures, people tend to consume and increase the consumption. So, it is a continuous process, and it has to be left the natural propensity of the human beings, citizens.

Sir, I am informed that the Ministry of Urban Affairs and Employment how now brought out a Vulnerability Atlas of India which maps out all disaster-prone areas with respect to earthquake, cyclones and floods. This would be a very useful tool for the State and district administrations for planning to reduce the impact of natural hazards and reduce the losses to houses, buildings and infrastructure and also of human lives.

Houses and buildings can be strengthened as per the technical guidelines issued so that the loss of life will also be reduced and the damage to houses will be minimised. The publication of this Atlas will help in taking pro-active measures for disaster mitigation rather than in responding to post-disaster relief measures and need and in doing only crisis management.

Similarly, about raising of the level of villages, we discussed this in Assam too, that ponds can be created in the vicinity of villages, and the silt taken out can be used to raise the level of the villages so that in an emergency this can be used as raised platforms by the population affected.

There are 2,900 large dams in India, whose storage does abate the floods. This has been the experience. Therefore, they are called multipurpose projects. Presently 700 large dams are under construction. All this storage does go to mitigate the people's sufferings.

So far as the PM's Relief Fund is concerned, it is a trust. It cannot be discussed in Parliament. The norms etc. are obviously matters within the purview of the trust. Under the Rules of Rajya Sabha, this cannot be discussed here because it has not been formed out of the Consolidated Fund of India. It has been formed through donations from vuluntary agencies. The relevant rule is rule 47 (a).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): That is there. We know it.

SHRI SOMPAL: Therefore, it cann be discussed.

With these words, Sir, I thank all the Members for their indulgence, for

showing their concern about these calamities and for making useful suggestions for coming out with better measures and evolving new codes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): What do you want to say? ..*(Interruptions)*..

SHRI SOMPAL: Just a minute, please.

In the end, I would like to felicitate Mr. Shamsher Singh Surejewala who is retiring on a very successful completion of his term in Rajya Sabha. He has been a veteran politician known to me since my childhood. He is a farmer by birth, by profession and by heart. He has held very senior and responsible positions in the Haryana Government as senior Cabinet Minister for a long time. Several times he very narrowly missed the Chief Ministership, which I always lament. His affection for me is also very dear to me. He has been guiding me, he has been inspiring me and he has always been indulgent in my cause.

With these words, I again wish him well. I again wish that he comes back to the House whenever the political situation permits so. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Hon. Members, on behalf of all the Members of the House, I feel pleasure in wishing Shri Surjewala all success in life and good health.

The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at thirtysix minutes past nine of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 30th July, 1998.